ने यूनिलैटरल डिक्लेरेशन आफ इंडिपेंडेंस कर के सत्ता अपने हाथ में ले ली है ।

इस लिए मैं चाहता हूं कि इस विषय पर कोई बात कहते समय सरकार इस असलियत को अपनी नजर के सामने रखे । आज भी रोडेशिया की आजादी के लिए लड़ने वाले सैकड़ों लोग सालिसबरी की जेलों में पड़े हुए हैं, जिन को सहारा देने वाले लोग दुनिया के किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में, नहीं बचे हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को सहारा देने और अफ्रीका की जनता की आजादी की लड़ाई में उस का समर्थन और मदद करने के काम में हिन्दुस्तान और अधिक गतिशील हो और इस के लिये नये कदम उठाये ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव को मन्जूर किया जाये । कांग्रेस के जिन सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का अपनी तकरीरों में समर्थन किया था, वे अपने विचारों को ठोस रूप देने के लिए अब भी इस प्रस्ताव का पूरा पूरा समर्थन करें और सरकार को यह ताकीद करें कि हम कामनवैल्थ से बाहर निकल आयें और अफ्रीका, और खास तौर से रोडेशिया, की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों का पूरा समर्थन करें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will now put the Amendment of Shri Bibhuti Bishra to the vote of the House.

The question is:

"That in the resolution,—

for "quit the Commonwealth of Nations forthwith in view of the inaction of the British Government against the illegal minority regime of Ian Smith."

substitute—

"press the British Government to use all possible means, including total economic sanctions to terminate this illegal regime as well as to urge the Security Council to act under Chapter 7 of the UN Charter and impose total mandatory sanctions against the Smith regime in Southern Rhodesia." (1)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will now put the main Resolution as amended by Shri Bibhuti Mishra's amendment.

The question is:

"This House condemns the execution of freedom fighters in South Rhodesia by the illegal regime of Ian Smith and urges the Government of India to press the British Government to use all possible means, including total economic sanctions to terminate this illegal regime as well as to urge the Security Council to act under Chapter 7 of the UN Charter and impose total mandatory sanctions against the Smith regime in Southern Rhodesia." (*as amend.*)

The motion was adopted.

16.34 hrs.

RESOLUTION *RE.* TRADE IN FOOD-GRAINS

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up Shri Mohan Swarup's Resolution. The time allotted is one hour. The next Resolution is also there and Food Debate is coming. I am not inclined to extend the time as far as possible.

SHRI S. XAVIER (TIRUNELVELI): Time should not be extended. Otherwise, I may not get my chance to move my Resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The discussion on the Demands for Grants of the Food Ministry is coming.

SHRI S. XAVIER: I will have some time to move my Resolution if the time-limit is strictly adhered.

AN HON. MEMBER: There is another Resolution also.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखीमपुर): वह भी फूड के बारे में है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: If that has also secured the ballot, what can I do?

श्री मोहन स्वरूप (नीलीभीत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "इस सभा की राय है कि अनाज के व्यापार का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।"

आप जानते हैं कि देश के 5,58,000 गांवों में रहने वाले अधिकांश लोग खेती करते हैं और . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का सम्बन्ध खाद्य और कृषि मंत्रालय से है, लेकिन इस मंत्रालय का कोई भी मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He will be coming in a minute.

SHRI M. A. KHAN (Kasganj): There is no quorum.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The bell may be rung—The bell may be rung a second time.—Now there is quorum.

Shri Mohan Swarup.

श्री मोहन स्वरूप: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जहां के 5 लाख 58 हजार गांवों के अधिकांश लोग खेती का व्यवसाय करते हैं और खेती से ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं तो जाहिर है कि वह अपनी उपज को बेचेंगे और आने वाले पैसे से अपना काम चलाएंगे। लेकिन आज तो व्यापार की व्यवस्था है इस वक्त वह एक अजीबोगरीब है। व्यापार कुछ ऐसे विशेष लोगों के हाथों में है जो कि गल्ले को अपने मनमानी ढंग से बेचते हैं और उसको स्टोर करते हैं। उसको जब चाहे तब बेचते हैं, जब चाहें तब खरीदते हैं। तस्करी करते हैं उस गल्ले की, उसमें मिलावट करते हैं और दुनियां भर का ऐसा कौन सा काम है, कौन सा पाप है जो कि यह व्यापारी नहीं करते? जब चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष चल रहा था तो मेरी कांस्टीट्यूएंसी में कुछ लोगों ने चीन को नेपाल के द्वारा चीनी और गल्ला बेचा। उपाध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं इससे अधिक और देशद्रोह क्या हो सकता है? अभी रूरल क्रेडिट कमेटी ने एक सर्वेक्षण किया था 1950–51 में तो उन्होंने बताया था कि गांव के लोगों के लिये 750 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ऋण लेने के सिलसिले में। उसके बाद वह आवश्यकता फिर 1000 करोड़ और 1200 करोड़ से ऊपर ढ़ गई 1958–59 में और अब तो शायद वह 2000 करोड़ रुपये से अधिक है। आप समझते हैं कि किसान या तो अपने गल्ले पर आधारित है या ऋण कहीं से पाये उस पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में जब कि उनका इस तरह से शोषण हो रहा हो, और यह जो व्यापारी हैं इनका एक ही काम है कि किसान से सस्ते मूल्य पर गल्ला खरीदें, जब किसान पास गल्ला होता है तो दाम गिर जाते हैं और जब किसान के घर से गल्ला व्यापारी के घर चला जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके मूल्य ढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उनका एक ही काम है कि सस्ते दर पर गल्ला किसान से खरीदें और उपभोक्ता को महंगे दामों पर दें। इससे न तो किसान को ही राहत मिलती है और उपभोक्ता का गला अलग से कटता है। जाहिर है कि खाद्यान्न में मुनाफा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। उनका जो खर्चा होता है, लाने ले जाने का, स्टोर करने का

और जो कुछ उसमें घाटा हो जाय, चूहे खा जायं या और तरह से नुकसान हो जाय उसको निकाल कर 5 प्रतिशत से अधिक मुनाफा नहीं होना चाहिये । लेकिन आजकल वह 50 प्रतिशत और कभी कभी तो सौ प्रतिशत तक मुनाफा कमाते हैं । 70 रुपये की बोरी गेहूं की खरीदी गई सन् 66 में और सन् 67 में आकर 150 रुपये पर बेची गई । तो करीब करीब सौ प्रतिशत तक मुनाफा यह कमाते हैं । ऐसी स्थिति में दोनों का शोषण हो रहा है, किसान का भी और उपभोक्ता का भी । इसलिये सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिये । मैंने सुझाव दिया है कि यह व्यापार इनके हाथ से ले लिया जाय और एक ऐसी सस्था बनाई जाय जो कि इस कार्य को अपने हाथ में ले सके । खाद्यान्न का जो पिछला साल गुजरा है वह बड़ी परेशानी वाला गुजरा है । इस साल खाद्यान्न की स्थिति कुछ सुधरी है । इस साल 90 मिलियन टन से ले कर 100 मिलियन टन तक गल्ला इस देश में होगा । ऐसी स्थिति में हम अपना खाद्यान्न का जो कारोबार है उसको अगर अच्छे ढंग से चलायें बजाय इसके कि इन लोगों के हाथ में यह रहे तो बहुत कुछ हालत सुधर सकती है ।

आप जानते हैं कि बाजार तीन चार तरह के होते हैं । एक गांव का बाजार होता है जिसमें कि हफ्ते में एक या दो बाजार होते हैं । इसके बाद कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो घोड़े से या गाड़ी से गल्ला ले जाते हैं और फिर मंडी होती है । मंडी के बाद एक होलसेस मार्केट होता है जो कि जिले के स्तर पर होता है । इन सारी चीजों में शुरू से लेकर आखीर तक करप्शन चल रहा है । जब होलसेल मार्केट में किसान गल्ला ले कर जाता है तो वहां आढ़तिये होते हैं, दलाल होते हैं । दलाल अपनी दलाली वसूल करते हैं, आढ़तिये अपनी आढ़ती वसूल करते हैं, तौलने वाला अलग अपनी मजदूरी वसूल करता है । इस तरह से चारों तरफ से उसका वहां पर शोषण होता है शुरू से लेकर आखीर तक । अब समय आ गया है कि उसको खत्म करना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में कई चीजें हमारे सामने आती हैं । पहली बात तो यह है कि एक नेशनल संस्था ऐसी बनानी चाहिये और एक बफर स्टाक बनाना चाहिये । ऐग्रीकल्चर प्राइज कमीशन की रिपोर्ट और एक फूड ग्रेन पालिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है जो 1966 में हुई है और वह 1967–68 में अभी हाल ही हुई है । इन कमेटीज की रिपोर्टें हमारे सामने आई हैं । इनके अनुसार यह कहा जाता है बफर स्टाक हमारा बनना चाहिए और मिलियन टन का कम से कम होना चाहिये । इसके बाद कहा जाता है कि प्रोक्योरमेंट भी होना चाहिये । प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं कि 8 मिलियन टन हर साल हो जाना चाहिये । वह कहते हैं कि डिकेड्स तक, काफी अरसे तक गल्ले का भाव इस तरह से रहेगा तो उस क्षेत्र में प्रोक्योरमेंट होना चाहिए । उसी के साथ साथ इन्टर-स्टेट मूवमेंट भी एक अवश्यक बात समझी गई है । लेकिन उस में भी रुकावट पड़ रही है क्योंकि फूड कारपोरेशन एक है हमारे यहां । वह काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है । और उसी के साथ साथ जोनिंग सिस्टम है जिस की वजह से इन्टर-स्टेट गल्ले का मूवमेंट नहीं हो रहा है । अभी अभी उत्तर में एक बड़ा जोन बनाया है लेकिन दक्षिण में या मध्य भारत में और कहीं भी बड़ा जोन नहीं है । उत्तर प्रदेश को भी जो बड़ा जोन अभी बनाया है पंजाब हिमाचल प्रदेश हरयाणा वगैरह का उस में नहीं लिया गया है । तो इस तरह से भी जो इन्टर स्टेट मूवमेंट है गल्ले का उस में रुकावट पड़ रही है, जोनल सिस्टम की वजह से इसके बाद एक प्राइस फिक्सेशन कमेटी बनी हुई है फूड मिनिस्ट्री के अन्तर्गत जो कि प्राइस का सर्वेक्षण करती है और कीमतों का निर्धारण करती है । लेकिन वह भी कुछ सक्रिय तरीके से कार्यवाही नहीं कर रही है । तो यह जो चीजें हैं जिन की आज आवश्यकतायें हैं उन की पूर्ति करने के लिये

[श्री मीठन स्वरूप]

कोई एक संस्था ऐसी नहीं है हमारे पास जो इन सारे कामों को इकट्ठा कर के सामूहिक तरीके से कर सके। मेरा सुझाव है कि हमारे यहां जो फूड कारपोरेशन है उस का कार्यक्रम विस्तृत किया जाय। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस का दफ्तर मद्रास में है जो कि देश के दूसरे सिरे पर है और उस की जो कार्यशैली अब तक रही है वह विफल रही है। तो मैं चाहता हूं कि उस को ठीक तरीके से कार्य करने के ढंग पर लाया जाय। उस का दफ्तर चाहे मध्य भारत में या उत्तर भारत में जहां कहीं मुनासिब हो वहां रखा जाय, देश के एक सिरे से हटा कर बीच में रखा जाय तो बेहतर है। इस के साथ साथ मैं चाहता हूं कि जो सारी चीजें मैंने बतायी इन सारी कार्यवाहियों को करने के लिए उस को उत्तरदायी बनाया जाय। मैं चाहता हूं कि उस का दफ्तर जोनल दफ्तर बने। हर राज्य में बने और उसी के साथ साथ हर जिले में उस को विस्तृत कर के उस का दफ्तर बनना चाहिये। उस की कार्यशैली इस तरह की होनी चाहिये, जैसी कि गन्ने के महकमे की होती है। गन्ने का जो विभाग है, वह गन्ना भी देता है, किसानों को कर्जा भी देता है, साथ ही साथ वह गन्ने को ले कर मिलों को भी देता है, ये तीन काम करता है। इसी तरह का फूड कारपोरेशन का कार्य होना चाहिये, वह किसानों से गल्ला वसूल करे, उन को मुनासिब कीमत दे, उपभोक्ताओं को भी मुनासिब दरों पर गल्ला मिल सके इस बात की वह गारन्टी करे। इस के लिये फूड कारपोरेशन को सक्रिय बनना होगा।

मैं चाहता हूं कि इसी के साथ साथ जो नेशनल सीड कार्पोरेशन है, उस को भी इसी में जोड़ कर इन की एक संस्था बना दी जाय। फूड कारपोरेशन और नेशनल सीड कारपोरेशन दोनों मिल कर इस कार्य को उठायें। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाय तो जो बातें मैंने यहां पर पेश की हैं, चाहे प्रोक्योरमेंट का सवाल है, बफर स्टाक का सवाल है, इन्टर स्टेट मूवमेंट का सवाल है इन सब के लिये इस प्रकार की संस्था अच्छी तरह से काम कर सकेगी।

एक चीज और है जो कि विचारणीय है। प्राइस फिक्सेशन बोर्ड आज तक कोई नहीं बना है। यह बहुत ही आवश्यक है कि इस तरह की संस्था बने जो कि गल्ले के मूल्य का निर्धारण करे इस में किसानों के भी प्रतिनिधि हों, गवर्नमेंट के भी प्रतिनिधि हों, और चूंकि हम नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, इसलिये नेशनल सीड कार्पोरेशन और फूड कारपोरेशन के भी प्रतिनिधि हों और वे बैठ कर तीन महीने के हिसाब से गल्ले के मूल्य का निर्धारण करें कि मई-जून, जुलाई में यह भाव होगा, उस के बाद आगे आने वाले महीनों में यह होगा, क्योंकि गल्ले के साथ सप्लाई एण्ड डिमाण्ड का प्रश्न भी आता है। उस के बाद गल्ले का ग्रेडिंग किया जाय—फर्स्ट, सैकेन्ड और थर्ड—तीन ग्रेडिंग होंगे, इसके अनुसार जब गल्ले के भाव का निर्धारण हो जायगा, तो किसान इस बात के लिये बड़ी खुशी से तैयार हो जायेगा कि वह अपनी उपज को खेतों से ले जा कर फूड कारपोरेशन को जो कि जिले में होगी, दे दे।

इसी के साथ साथ रिबेट की भी व्यवस्था होनी चाहिये। किसान को दो परसेन्ट या तीन परसेन्ट रिबेट गल्ले पर मिल सके। इस से उस को प्रोत्साहन मिल सकेगा और वह बड़ी खुशी से गल्ले को दे सकेगा। मैं समझता हूं कि गल्ले के व्यापार को अगर इस स्तर पर लाया जाय, तो प्रोक्योरमेन्ट का जो सवाल है, वह हल हो सकता है, बफर स्टाक बन सकता है, किसान को अच्छा मूल्य मिल सकता है और साथ ही साथ उपभोक्ता को भी खाने के लिये गल्ला ठीक दामों पर मिल सकता है। इस व्यवस्था से, आज जो शोषण हो रहा है, जिस की वजह से सारे लोग—चाहे उपभोक्ता हों

या किसान—पीड़ित हैं, परेशान हैं, वह दूर हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बताऊं कि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी उत्पादित की हुई वस्तु का भाव स्वयं निर्धारित नहीं करता है, बल्कि उस का निर्धारण खरीदार करता है । आज जो चीजें मिलों में उत्पादित होती हैं, चाहे बक्स बनते हों, चाहे जूते बनते हों, वहां पर निर्माता उन चीजों के दाम निर्धारित करता है, लेकिन किसान अपनी उत्पादित चीजों का दाम स्वयं निर्धारित नहीं कर पाता है, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है । अब इस का अन्त होना चाहिये । जो बातें ब्रिटिश शासनकाल से अब तक चली आ रही हैं, उन को खत्म कर के एक नई सूरत पैदा करनी चाहिये जिस से कि हमारा देश तरक्की कर सके ।

गल्ले के बारे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं समझता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करेगी और इस के राष्ट्रीयकरण की तरफ सक्रिय पग बढ़ायेगी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Resolution moved:

> 'This House is of opinion that trade in foodgrains be nationalised immediately."

As I have said, one hour only has been allotted for this because the subject of the next Resolution is also almost the same. Therefore what I suggest is that we will accommodate a few speakers on this and a few on the next one. Each Member will have just five minutes.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would begin by saying that the title of this Resolution is incorrect because, as our hon. Member proceeded to explain, his idea of nationalisation is 4 million tonnes of buffer stock and 8 million tonnes of foodgrains supply to the public. This is a little more than the present system and our friend, therefore, has not really advanced as far as the Communist to suggest total nationalisation of trade. But even this partial trade in grains has done no good to anyone. One has to inquire which class has benefited from Government's purchase of foodgrains. As far as the cultivator is concerned, though I do not see many representatives here, they have the grievance that they are paid only a fraction of the price at which Government sells and at which the market sells the grain which is bought from them. Is it fair, as our hon. Member considered that he is speaking for the cultivators, that they should be deprived of a proper price?

The second class consists of the traders. He has very rightly condemned them. I do not know how many traders are represented here.

SHRI SHASHIBHUSHAN BAJPAI (Khargone): Only you are there.

SHRI LOBO PRABHU: I am not a trader.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): You are their advocate.

SHRI LOBO PRABHU: I am the advocate of honest traders and of honest people.

The question is, if today the traders are dishonest—they are—it is because there is no competition. Government itself is to blame that has reduced the quantity of food supply coming to the market. Government itself is to blame that prices are always rising. So long as prices rise there is a tendency to hoard, to profiteer and even to blackmarket. So, if there is anyone to be blamed for the dishonesty of the trade, it is the Government.

The third is the class of consumers. Consumers can be placed in two categories—the rich like our friends and the poor like our friends there.

SHRI SHEO NARAIN: Are you poor?

SHRI LOBO PRABHU: There are no rich men here.

As far as the rich are concerned, controls do not touch them very much because they are able to purchase whatever they want; they are only corrupted. Controls corrupt the rich because they give a scope, a free play to the power of their money. As far as the poor are concerned, I would like people to understand what it means to stand for hours in a queue which one could find at any time in the past when there was genuine scarcity of grains. For them to lose a day, sometimes even more, for a handful of grain, I think, is one of the tragedies of our administration, something about which the Food Ministry should be thoroughly ashamed that not only have they got to wait that long and pay a price much higher than what has been paid to the cultivator but they have to get grain which in a good part is not grain at all but is sand and stone. So, the poor are the sufferers here again.

Therefore, if our friend thinks that nationalisation is going to do good to anyone, he is not thinking of any people in this country except perhaps the smugglers and the corrupt government servants.

He has, luckily for this House, proposed the abolition of zones. He has proposed also that inter-State movement should be free. That is certainly an advance on the thinking of Government on this subject. Government has only enlarged one zone. Government should enlarge all zones. Shri Somani, no doubt, will speak more about it. But I would just like to ask this of Government: What is the benefit of these zones? Is it their interest to create pockets of scarcity, vacuums to which the grain is sucked at a rate and at a price which is always rising? If the idea of Government is to raise prices, then zones and inter-State bans have a purpose. If not, they are only in favour of smugglers who, at every border, are able to bring the grain, pay the police and get sometimes, as in my district, across to Kerala, a price twice or thrice that they pay for it.

17 hrs.

Let us just think in terms of abolishing the zones. If prices fall, zones will become redundant because there will be pressure, I have no doubt my hon. friend, from Haryana, will press for abolition of zones because they are unfair to the growers that the prices should be restricted on one side of a line. If prices fall, zones will go. If prices do not fall, zones will stay and prices will rise further. I for one see that the prices will fall and the fall in prices is going to have consequences which have not been considered in this House. If Government keeps a large stock, and they are providing Rs. 720 crores for the grain trade, if the prices fall by anything like 10 per cent on the prices paid by Government, there will be a loss of Rs. 72 crores. This loss to the Government is a loss to the people. Government pays nothing from the pockets of Ministers. Government pays from the pockets of the people. Therefore, whether the prices rise or fall, controls are bad. Nationalisation of trade is bad. Free competition is the passport to a better order of things.

17.02 hrs.

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair*]

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Minister at least some points on which I would like to be enlightened.

The Food Corporation of India is doing a very good job. But I would urge upon the Minister to let us know this. In recent times, there has been some thing going on in the Food Corporation itself which was brought to

the notice of the public by its ex-Chairman. Today, the Food Corporation cannot afford to function itself as a body dominated by certain bureaucrats because it is now competing with a large number of private traders. During the last so many years, the private traders in foodgrains have exploited the producers of foodgrains which my hon. friend, Shri Mohan Swarup, has tried his best to bring to light by moving this Resolution

The Food Corporation's activities have been expanded and it has gone over to as many as 14 States. It is a good thing. In Haryana, in the last few months, there was a distress sale of wheat. In the beginning, the Haryana Government did not like to invite the Food Corporation. But in later period, when there was a distress sale, when the wheat prices in Haryana which varied between Rs. 100 to Rs. 115 a quintal at the time of the harvest and which were expected to rise further to Rs. 124 a quintal, when these crashed immediately during the lean period and came down to Rs. 70 to Rs. 75 a quintal, the Haryana Government sent an SOS to the Food Corporation asking them to enter the market immediately. Then, the Food Corporation entered the market and saved the situation.

Here, the question arises that the Food Corporation, according to the present calculations, would require a working capital of nearly Rs. 200 crores at the peak operation during the season. The Food Corporation had fixed a target of procuring 6 million tonnes this year, and the procurement target was fixed at 5 million tonnes by March, 1968. We would like to know from the hon. Minister whether really this procurement target, by March, 1968, of five million tonnes has been fulfilled. I know that it has not been fulfilled. I have got reports from certain State Governments—and I can bring it to the notice of the hon. Minister—that the procurement has failed. Let me cite the instance of that Government, which is run by the Party of Mr. Lobo Prabhu, i.e., the State Government of Orissa, where Swatantra is ruling. The hon. Minister will please let us know whether the hon. Chief Minister of Orissa has already informed the Government of India that the procurement in Orissa is not progressing satisfactorily because the millowners are not co-operating with the Food Corporation there. I hope, the hon. Minister will agree at least that such a letter has come from the Chief Minister to the Ministry here. If this is the position then we would like to know what steps Government of India are taking to activise procurement in that State and in such other States where the millowners are not co-operating.

One more point and I will have finished and that is with regard to one anomaly that we have. India is trying to win the battle of economic independence on all fronts and also on the food front. But I am completely surprised over this. India was importing 11 million tonnes of foodgrains when there was drought, and India is now importing nearly 8 million tonnes of foodgrains when according to Government of India this is one of the bumper crop years in India and that the production has gone up from 95 million to 100 million tonnes. How is it that the more the production increases, the more the import also increases? How is it that a procurement, in a bumper crop year of 95 or 100 million tonnes, has been fixed at only 5 million tonnes by March, 1968 whereas the Agricultural Prices Commission suggested a procurement target of 8 million tonnes? I do not want to take much time of the House. I would request the hon. Minister to enlighten us on this, and I hope that the hon. Minister will try his best to help the Food Corporation of India in expanding its activities. Whatever difficulties or whatever deficiencies may be there, it is because that the Food Corporation has come in, that at least the producers are getting a better price today. A total trade in foodgrains of about Rs. 2,600 crores is controlled by private traders, and I would

[Shri Chintamani Panigrahi]

urge on the hon. Minister that the Government of India should gradually increase the scope of the Food Corporation of India, so that in the near future, the trade is nationalised. This is one of the ten points that the AICC has accepted; the Congress has given a promise to the people that, in the near future, more and more trade will be nationalised, in the sense that it will be in the public sector, and the profiteering, hoarding and black-marketing resorted to by the private traders, should end and the producer should get the reasonable price for his produce.

श्री बेणीशंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय, जिस समय दो वर्ष के सूखे के बाद और भुखमरी के बाद देश में कुछ अन्न पैदा हुआ है और लोग यह आशा करते हैं कि रीजनल जोन्स हटा दिये जायेंगे जिनकी वजह से आज देश के लोगों को जितना अन्न मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है, उस समय श्री मोहन स्वरूप जी का यह प्रस्ताव कुछ ऐसा है जिसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता । उन्होंने कहा है कि हमारे 5 लाख 58 हजार गांवों में खाद्यान्न हम किस तरीके से पहुंचायें यह एक समस्या है । लेकिन मेरे वह मित्र यह भूल गये कि ये गांव ही हैं जहां अन्न पैदा होता है । अगर हम अन्न के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो सारा अन्न गांवों से खिंच कर शहरों में आयेगा जिससे लोगों की तकलीफें घटने के बदले बढ़ जायेंगी ।

अभी देश में पार्शियल कंट्रोल की स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि सरकारी गोदामों में पड़ा हुआ अनाज किस तरह बर्बाद होता है और लोगों तक नहीं पहुंच पाता । कलकत्ते में हमने देखा है और अमृत बाजार पत्रिका में कुछ दिन पहले यह रिपोर्ट निकली थी कि बाहर से अमरीका से जो गेहूं आता है उसका करीब-करीब 10 प्रतिशत: हिस्सा थ्रू दी ब्रेंस चला जाकर बर्बाद हो जाता था । इसका कारण यह था कि वहां लोगों को उसके प्रति मोह नहीं था । सरकारी कर्मचारी जोकि उसमें काम करते थे उन्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं थी कि अनाज सड़ व बर्बाद हो रहा है । उन्हें उसके द्वारा नुकसान होने की कोई चिन्ता नहीं थी और पर्वाह नहीं थी कि यह नुकसान किसका हो रहा है ।

अनाज के राष्ट्रीयकरण की आज जो हाउस में चर्चा हो रही है अगर इसकी मांग श्री बनर्जी करते तो वह समझ में आ सकती थी । कम्युनिस्ट मित्र भी ऐसी मांग करते तो मैं उनको भी समझ सकता था क्योंकि वे लोग सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं । उत्पादन का राष्ट्रीयकरण हो, अन्न के व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो, कपड़े के व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो, सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण हो लेकिन मैं इस तरह के एक ऐसे पार्शियल राष्ट्रीयकरण की बात को नहीं समझ सकता हूं क्योंकि इससे देश में कितनी ही परेशानियां बढ़ जायेंगी और इससे कितने लोगों के कष्ट बढ़ जायेंगे जिसका कि कोई हिसाब नहीं है ।

वांछनीय तो यह है कि कोई भी प्रस्ताव हो कोई भी कार्य हो उसमें लोगों का और जनता का हित होना चाहिये । अब मेरे माननीय मित्र अपने इस प्रस्ताव से किन लोगों का हित करना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

हम ने आज कलकत्ते में अनाज की स्थिति को देखा है । कलकत्ते में फूड कंट्रोल है और जब हमारे यहां रोटी का अभाव था तो ग्रैंड होटल और ग्रेट ईस्टर्न होटल के सामने 2, 2 मील की लम्बी कतार खड़ी देखते थे और उस हालत को देख कर कलेजा मुंह को आता था । मुझे इस बारे में एक कहानी याद आ रही है कि कोई एक हमारे मित्र जोकि यहां से उस गये थे जब वह वहां एक रूसी दम्पत्ति के यहां गये और उन्होंने घर में मौजूद लड़के से पूछा कि तुम्हारे पिता जी कहां हैं तो उसने जवाब

दिया कि वह स्पेस में हैं । जब उस लड़के से पूछा गया कि उसकी माता जी कहां हैं तो उसने जवाब दिया कि वह रोटी लेने गई है । यह पूछे जाने पर कि उन दोनों में से पहले कौन आयेगा लड़के ने जवाब दिया कि पिता जी पहले आयेंगे माता जी पीछे आयेंगी । अब रूस में जहां नेशनलाइजेशन का या राष्ट्रीयकरण का इतने दिनों से प्रचार हो रहा है और उस पर व्यावहारिक रूप से अमल किया जा रहा है जब वहां यह अवस्था है तो हम लोगों की क्या उस हालत में क्या अवस्था होगी यह मेरी समझ से बाहर की चीज है ।

सभापति महोदय, अभी हमारे यहां कई क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण हुआ है । बिहार और बंगाल में बस ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण किया गया है । जो बसें वहां चलती हैं वे करीब-करीब सब राज्य के कंट्रोल के अन्तर्गत हैं। लेकिन आज वहां करोड़ों रुपये की सरकारी पूंजी लगा कर भी क्या उसमें आय होती है और क्या उसमें बचत होती है ? मैं बंगाल की बात जानता हूं बिहार की बात जानता हूं । दोनों जगह इस बस ट्रान्सपोर्ट के नेशनलाइजेशन के धंधे में सरकार को नुकसान हो रहा है । यहां पर अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं वह इस बात को जानते होंगे कि हमारे सरदार कलकत्ते में और दूसरी जगह जो बस चलाते हैं वह 10–12 हजार रुपया साल में कमा लेते थे और अपने परिवार आदि का पालन करते थे लेकिन जब से इन सरदार लोगों को हटा करके यह बसों का राष्ट्रीयकरण किया गया वहां करीब-करीब 900–1000 बसों का फ्लीट और करोड़ों की पूंजी उसमें सरकार ने लगाई तो आज उसमें नुकसान हो रहा है । आज आप उन बसों को शकल देखिये, वह टूटी फूटी हैं, किसी की खिड़की नहीं है तो किसी का दरवाजा नहीं है । ऐसी हालत हमारे इस बस राष्ट्रीयकरण उद्योग की वहां पर हो रही है । ऐसी अवस्था में अगर हम खाद्यान्न का भी राष्ट्रीयकरण करते हैं तो मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि लोग भूखों मर जायेंगे ।

अभी हमारे माननीय मित्र ने व्यापारियों में करप्शन की चर्चा की है । मैं इससे इंकार नहीं करता कि व्यापारियों में भ्रष्टाचार नहीं है । व्यापारियों में भ्रष्टाचार है लेकिन उनमें उस भ्रष्टाचार की वजह क्या है क्या इस ओर भी आप ने ध्यान दिया है ? अगर आप यह कंट्रोल हटा देंगे तो भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । मुझे कहने के लिये क्षमा किया जाय कि इन 20 वर्षों में कंट्रोल्स की वजह से अपराधों की संख्या बढ़ी है वरना व्यापार वह चीज है कि अगर ट्रेड फ्री कर दी जाय और कोई कंट्रोल न रहे तो व्यापारियों में एक फ्री ऐंड हैल्दी कम्पटीशन पैदा होगा और वह कम से कम प्राफिट पर अपने माल को कंज्यूमर्स को बेचेंगे ।

आज आप कहते है कि राजस्थान में चना 25 रुपये मन मिलता है जबकि हमारे यहां बिहार में सत्तू खाने के लिये लोगों को चने की आवश्यकता होती है तो वही चना हमारे वहां 80–90 रुपये मन मिलता है । इस तरह से अधिक मुनाफ़ा कमाने की कुछ लोगों की टैंडेन्सी है उसको आप रोक नहीं सकते हैं । वहां राजस्थान में 25 रुपये मन चना मिलता है और वह 25 के बदले में उसे बिहार में 88 रुपये मन में बेचते हैं । लेकिन जैसा मैंने कहा अगर आप इसमें फ्री कम्पटीशन, कर दें तो होगा यह कि कुछ लोग 25 रुपये मन में वहां से लेंगे और अपना खर्चा आदि लगा कर उसे 35 रुपये में बेचेंगे, कुछ 40 रुपये में बेचेंगे और हो सकता है कि कोई भाई खर्चा और कुछ मुनाफ़ा लगाकर 38 रुपये मन में बिहार में बेच दंगे । कुछ 36 रुपये में ही बेच देंगे । अब इसमें भ्रष्टाचार का सवाल कहां उठता है ? भ्रष्टाचार तभी होता है जब आप कहते हैं कि तुम राजस्थान में 25 रुपये मन चना खरीदते हो तो उसे 25 रुपये पर ही क्यों नहीं बेचते हो । इसलिये जाहिर है कि जितने में

[श्री वैद्यनाथन शर्मा]

उसने खरीदा है उतने में कैसे वह बेच सकता है ? उसका खर्चा लग जाता है और फिर वह धंधा जो करता है तो चार पैसे कमाने के लिये ही तो करता है । इसलिये जैसा मैंने पहले कहा अगर आप करप्शन को हटाना चाहते हैं तो सब से पहले कंट्रोलों को हटाना पड़ेगा । स्वामी विवेकानन्द जी ने एक बार कहा था : "यू कैन नौट लेजिस्लेट फोर वरचू" । आप अच्छे काम के लिये कोई कानून नहीं बना सकते हैं । अच्छे काम के लिये आप को एक वातावरण तैयार करना होगा । अगर आप खाद्यान्न के व्यापार से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो सब से पहले आप को कंट्रोलों को उठाना होगा । सब से पहले जोनल मूवमेंट जो व्यापार का है उसको हटाना होगा फिर आप देखिये कि कहां भ्रष्टाचार है और कहां अनाचार है ?

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): Mr. Chairman, Sir, I whole-heartedly appreciate the spirit in the Resolution and congratulate Shri Mohan Swarup for bringing forward this outstanding resolution. This is an old demand and age-old demand of the poor peasantry, who have been so much pressed and oppressed by vested interests, by feudal lords and big landlords since time immemorial. You must remember, Mr. Chairman, that peasantry in our country are a class of absolutely exploited people. They are the forerunners and yet they have always been relegated to the background and no avenues of development or progress were made available to them. In this era, when we are free, there is a genuine demand that the peasantry, the poor farmer, should be given the proper place. And that proper place can only be given if they get their due, for their produce. It is an admitted fact. Whatever the peasant is investing, he is not getting his proper return. This issue involves fundamental issues of justice, fairplay, equity and ethics also. Why should a man who puts such a hard labour day in and day out, in season and out of season, in chilly winter and scorching heat, who is down to the earth and who has done strenuous and hard work, be deprived of his labour? A man who is putting his labour must get due return for that.

It is very important that this particular sphere of marketing of his foodgrains should be taken note of by the Minister in charge of Food and Agriculture. It is good luck, Sir, that a progressive farmer is at the helm of affairs. Mr. Shinde himself is a farmer, and our Cabinet Minister, Shri Jagjiwan Ram is a farmer, and both of them come from Bihar, the core of the peasantry. I am proud of this, Sir. And much of our hope is pinned on them. It is high time that they appreciate the crying need of the country. They will go down in history as the saviours of the poor peasantry, by taking up the cause of nationalisation of food trade.

The marketing centres have become forums of loot, forums of exploitation and forums of butchery of the poor peasantry to deprive them of whatever they are entitled to. The middlemen earn not only 100 per cent but even 200 or 300 or 500 per cent of what they are investing as profits. These middlemen must go. I am not against the petty shopkeepers or the small people who are poor people. But I am referring to the class of hoarders which has come to stay. Their main job is to create scarcity in the country by acting as parasites on the blood of the poorer sections of society, and they are piling up huge profits.

My request is that the peasant must get his due return. So far as the prices are concerned, he should get better prices, and whatever e wants to purchase such as cement, sugar, iron, cloth, fertilisers, electricity etc. should be made available to him at reasonable rates because he is being

burdened with innumerable taxes, canal rates, *chaara lagaan*, local rates electricity tax and so on.

This is the time when in free India people like the present hon. Minister are in power and when a party like the Congress is in office, whose aim is to bring about democratic socialism and this is the time when they should do something for the peasantry. 80 per cent of the population of our country is in rural areas, and it is heralded by the peasantry and they should be made citizen No. 1 in the country. They should be affluent and they should be free from the scourge of want and exploitation.

I wholeheartedly support the resolution moved by my hon. friend.

SHRI K. M. ABRAHAM (Kottayam): The middlemen in the food trade are appropriating the bulk of the profits in foodgrains trade. They accumulate huge profits by purchasing foodgrains at a lower price and selling them at higher prices when the prices go up. The poor peasants who are the actual growers of the grains get lower prices and the consumers have to pay higher prices when they purchase from the market.

That is why we are demanding nationalisation of the food trade. The Central Government are not sincere in approaching this problem and solving it. They started the Food Corporation of India with a capital of Rs. 100 crores. But they have procured only 3 per cent of the needs of the total population of the country as a whole. There has been no co-ordinated approach with regard to the implementation of the national food policy. They have been discussing about a national food policy for the last so many years but nothing has emerged out of it so far because they are not ready to purchase or procure the surplus food from the hoarders and swindlers who are having it in the surplus States. The result is that the deficit States are suffering, and they are in an acute position and are in a starving condition.

The Centre is also using food as a weapon in politics. I am not going to argue about such things because this House has already discussed this on many an occasion. The instances of Kerala and Bengal have already been quoted here. I am not going into all that now.

If Government do not nationalise the food trade, immediately the people will think that Government are siding with the profiteers, blackmarketeers and landlords.

SHRI PILOO MODY (Godhra): The debate on this resolution must conclude at 5.30 p.m. There are two more resolutions after this.

MR. CHAIRMAN: This resolution was moved at 4.40 p.m. May I know how long the hon. Minister would like to take?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): About 8 to 9 minutes.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Shashibhushan Bajpai.

श्री शशि भूषण वाजपेयी (खारगोन) : सभापति महोदय, मैं श्री मोहन स्वरूप जी को, जो यह प्रस्ताव लाये हैं, मुबारकबाद देता हूं, खास तौर इसलिये कि पी०एस०पी० के ऐसे ही नेता सही नेतृत्व दे सकते हैं। मुझे यह आशा है कि माननीय सदस्य इसी प्रकार के प्रस्ताव हमेशा लाते रहेंगे ताकि देश में जागृति बढ़े।

जहां तक इस देश में आढ़तियों की कल्चरल बैकग्राउंड का सवाल है, जब तक यह आढ़तिये लोग इस देश से समाप्त नहीं किये जाते तब तक वह कोई भी दूसरा काम करने के लिये तैयार नहीं होंगे। नतीजा यह होता है कि कई लाख लोग सिर्फ इसी बात में लगे रहते हैं कि किस तरह से गांव वालों को लूटें और किस तरह से उनसे अनाज लेकर रख लें तथा महंगा से महंगा बेचें। उनके बच्चे पढ़ने लिखने में मन नहीं

[श्री शशि भूषण बाजपेयी]

लगाते । पढ़ने लिखने के बाद भी, बी० ए० एल० एल० बी० करने के बाद, डाक्टरी पास करने के बाद भी वह फिर आढ़तियों की दूकान पर आ कर बैठ जाते हैं । जब तक उनको इस तरीके से नहीं मारा जायेगा तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता । जैसा हमारे एक जन संघ के मित्र ने कहा; पिता तो अंतरिक्ष में चला गया और मां रोटी लेने चली गई । वह रोटी के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, अंतरिक्ष में कोई नहीं जा सकेगा । अगर इस देश के लोगों को अंतरिक्ष में भेजना है तो इन लाखों आदमियों को एक दूसरी दिशा में लाना होगा ।

राष्ट्रीयकरण के लिये कुछ चीजें बहुत आवश्यक हैं । जैसे हमारी राइस मिल्स हैं । इनका नैशनलाइजेशन होना चाहिये क्योंकि वह बहुत काफी स्टाक कर लेती हैं, बैंकों का भी नैशनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि बैंक अनाज के लिये बहुत पैसा देते हैं और अनाज रखवाते हैं । कई बार तो यह होता है कि जिन चीजों के लिये कहा जाता है कि बैंक में हैं, जिस चीज के रखने की एन्ट्री होती है किताबों में वह नहीं रखी जाती हैं, बल्कि दूसरी चीजें होती हैं । आज जो बड़े बड़े जागीरदार और राजे महाराजे गांवों में हैं वह बड़े बड़े वेअर हाउसेज तो नहीं बना सके, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी गढ़ियां हैं, उनके बड़े बड़े महल हैं, जो कि इस काम में आते हैं और गांवों का सारा अनाज उनमें रख लिया जाता है । जब तक इन राजे महाराजों की शक्ति कम नहीं की जाती है, तब तक हमारा काम नहीं चल सकता । आज भी इस देश में आढ़तियों को पैसा बैंकों में से आ कर इन राजे महाराजों के हाथों में आने लगा है ।

आज हमारा सीड कारपोरेशन बना हुआ है, उसमें देश के एक बहुत माने हुए नेता चेयरमैन बनाये गये । उसी तरह से फूड कारपोरेशन में जो लोग जनता के हितों की रक्षा कर सकते हैं, उनको लाना चाहिये, क्योंकि आने वाले वक्त में फूड कारपोरेशन को एक ऐतिहासिक रोल अदा करना है । इस तरह के जितने भी कारपोरेशन हमारे देश में बनाये गये हैं, दुर्भाग्य से उन सब के सलाहकार प्राइवेट सेक्टर से ला कर रखे गये । इसका नतीजा यह हुआ कि पब्लिक सेक्टर उतना नहीं बढ़ सका जितना कि बढ़ना चाहिये ।

आज कल जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के रास्ते में जो लोग रोड़े अटकाते हैं, वह यह आढ़ती लोग हैं और वही जागीरदारी के चौकीदार बन गये हैं क्योंकि उन लोगों की गढ़ियों में आढ़तियों को अपना माल रखने का मौका मिलता है । मैं चाहता हूं कि फूड जोन इस देश में खत्म कर दिये जायें क्योंकि अगर आढ़तियों को मौका दिया गया तो यह लोग सचमुच लोगों को भूखों मार देंगे । आज इन आढ़तियों के मुंह में मुनाफे का इतना खून लग चुका है कि यह लोग खुद भूखों मर लेंगे लेकिन अनाज जरूर गाड़ कर रखेंगे । मैली धोती पहनेंगे, मैली बनियान पहनेंगे लेकिन उनके पास करोड़ों रुपया होगा । उसके बावजूद भी अगर अनाज की कमी होगी तो उसको उन्होंने अपने गोदामों में भर कर रखा हुआ होगा । मैं चाहता हूं कि इन लोगों से बचाने के लिये, गरीब जनता को बचाने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाये । आढ़तियों का होना देश के लिये एक दुर्भाग्य की बात है । मैं चाहता हूं कि उन लोगों को सजा दी जाये जो इस तरह से होर्डिंग करके माल को अपने यहां छिपाये रखते हैं ।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं जो मेरे साथी कुंवर मोहन स्वरूप जी ने पेश किया है । चूंकि वक्त बहुत कम है इस वास्ते मैं इतनी ही गुजारिश करता हूं कि गल्ले की ट्रेड आढ़तियों की शक्ल में एक लानत बन कर रह गई है । एक तरफ तो ये आढ़ती

किसानों को लूटते हैं और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को लूटते हैं। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि जितना बैकवर्ड एरिया हो जितने गरीब किसान हों उतना ही ज्यादा उनको लूटा जाता है। मंडी में अगर किसान गल्ला लाता है तो बगैर आढ़ती की दलाली से उसको वह बेच नहीं सकता है। उसकी गाड़ी जब आढ़ती के यहां पहुंचती है तो आप देखें कि उससे कितना ही पैसा धर्म खातों के नाम पर वसूल किया जाता है। कहा जाता है कि यह गोशाला के लिये खाता है यह मंदिर के लिये खाता है, यह विधवा धर्म खाता है और न जाने कितने नामों से उन्होंने ये खाते खोल रखे हैं। यह कहा जाता है कि बिरला जी बड़े भारी दानी हैं या फलां आढ़ती बड़ा भारी दानी है और बहुत पुण्य करता है। लेकिन किस से पैसा ले कर यह पुण्य किया जाता है। इनके पैसों से ही तो यह किया जाता है, इनका पैसा ही तो लुटवाया जाता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उस पैसे से पोलिटिकल पार्टीज तक की मदद की जाती है। किसान को एक्सप्लायट करके जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वही पैसा तो यहां खर्च किया जाता है। कंज्यूमर्ज का भी इसी तरह से एक्सप्लायटेशन होता है।

मेरे खयाल में मेरे भाई अपनी कांस्टिट्युएंसी में जो थारू लोग कहलाते हैं जल्दी में उनकी बात को कहना भूल गये हैं। पीलीभीत और नेपाल की तराई में वे रहते हैं। इन बेचारे थारुओं के लिये ये आढ़ती सिर्फ मिट्टी का तेल और खाने के लिये थोड़ा सा चावल छोड़ देते हैं बाकी सब का सब उनसे वसूल कर लेते हैं। उनके बच्चे कर्जदार पैदा होते हैं और कर्जदार मरते हैं। एक तरफ तो किसानों की यह लूट चलती है इनकी तरफ से और किसानों को तबाह और बरबाद जिन्दगी भर के लिये कर दिया जाता है और दूसरी तरफ क्या होता है इसको भी आप देखें। मेरे अपने जिले का बाकया है कि 25 से 28 रुपये मन तक इन आढ़तियों ने किसानों से गल्ला खरीदा और उसको 60 रुपये मन से लेकर 66 रुपये मन तक के भाव पर बेचा। क्या इस बात को भुलाया जा सकता है कि जब जिला बनारस में—मुजफ्फरपुर में और बिहार में लोग भूखों मर रहे थे एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दे रहे थे उस वक्त इन आढ़तियों के मकानों में चावल की बोरियां, आटे की बोरियां छतों से बातें कर रही थीं।

इतना होने पर भी आज यहां पर इनकी वकालत की जाती है। इस बात पर गौर नहीं किया जाता है कि इनके जरिये से इस मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, कितनी तबाही हो रही है। गल्ले का व्यापार हमारे मुल्क का सब से बड़ा व्यापार है। लगभग दस करोड़ टन गल्ला इस मुल्क में खरीदा और बेचा जाता है जिस पर लगभग पांच अरब रुपये से ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है। यह जो मुनाफा है यह कौम के काम में आना चाहिये।

मैं मानता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में बहुत बुराइयां हैं बहुत ज्यादतियां होती हैं बुरे काम होते हैं बड़ा लास होता है। हमारे बुजुर्ग लोहिया प्रभु माहब ने कहा कि यह पब्लिक का ही तो नुकसान होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में जो कमियां हैं, उनको दूर करना भी तो हमारा फर्ज है। जब उसकी बात आयेगी तो उसको भी हम सख्ती के साथ क्रिटिसाइज करेंगे। उसको हम माफ नहीं करेंगे। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि चाहे कोई सरकारी इदारा हो या गैर सरकारी तीस रुपये मन गल्ला खरीद कर 66 रुपये मन बेचे या इस इंतजार में रहे कि कब गल्ला महंगा हो और कब बेचा जाये। लोग भूखों मरते रहें लेकिन वह इस गल्ले को दबा कर बैठा रहे।

मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसको पार्टी के नुक्ते नजर से न देखा जाये। इस तरह से न देखा जाये कि सुंदर मोहन स्वरूप जी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी की तरफ से यह प्रस्ताव आया है। मैं चाहता हूं कि पार्टी

[श्री इसहाक साम्भली]

लैवेल से ऊपर उठ कर हम को इस प्रस्ताव को एक राय से पास कर देना चाहिये । मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार तेजी के साथ इस तरफ कदम बढ़ाये । अगर वह ऐसा न करेगी तो एक तरफ तो कंज्यूमर्स की और दूसरी तरफ किसानों की लूट इसी तरह से चलती रहेगी । मुझे तो कई बार शुबहा होता है और यह एक कुदरती बात भी है कि कहीं सरकार को भी उन व्यापारियों के साथ मिली भगत तो नहीं है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस रेजोल्यूशन को इत्तिफाके राय से पास किया जाये और गल्ले की तिजारत को फौरी तौर पर नैशनलाइज़ किया जाये ।

[شری اسحاق سنبھلی (امروہا) :

میں اس پرستاو کا پر زور سمرتھن کرتا ہوں جو میرے ساتھی کنور موہن سروپ جی نے پیش کیا ہے - چونکہ وقت بہت کم ہے اس واسطے میں اتنی ہی گزارش کرتا ہوں کہ غلے کی ٹریڈ آڑھتیوں کی شکل میں ایک لعنت بن کر رہ گئی ہے - ایک طرف تو یہ آڑھتی کسانوں کو لوٹتے ہیں اور دوسری طرف کنزیومرز کو لوٹتے ہیں - میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ جتنا بیکورڈ ایریا ہو - جتنے غریب کسان ہوں - اتنا ہی زیادہ ان کو لوٹا جاتا ہے - منڈی میں اگر کسان غلہ لاتا ہے تو بغیر آڑھتی کی دلالی کے اس کو وہ بیچ نہیں سکتا ہے - اس کی گاڑی جب آڑھتی کے یہاں پہنچتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سے کتنا ہی پیسہ دھرم کھاتوں کے نام پر وصول کیا جاتا ہے - کہا جاتا ہے کہ یہ گوشالہ کے لئے کھاتا ہے، یہ مندر کے لئے کھاتا ہے - یہ دھرم دھرم کے لئے کھاتا ہے اور نہ جانے کتنے ناموں سے انہوں نے یہ کھاتے کھول رکھے ہیں - یہ کہا جاتا ہے کہ برلا جی بڑے بھاری دانی ہیں - یا فلاں آڑھتی بڑا بھاری دانی ہے اور بہت پنیہ کرتا ہے - لیکن کس سے پیسہ لے کر پنیہ کیا جاتا ہے - میں تو یہاں تک کہونگا کہ اس پیسے سے پولیٹیکل پارٹیز تک کی مدد کی جاتی ہے - کسان کو ایکسپلائٹ کرکے جو پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے ہی پیسہ تو یہاں خرچ کیا جاتا ہے - کنزیومرز کا بھی اسی طرح سے ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے -

میرے خیال میں میرے بھائی اپنی کنسٹیٹیوئنسی میں جو تھارو لوگ کہلاتے ہیں - جلدی میں انکی بات کو بھول گئے ہیں - پہاڑی بستی اور نیپال کی ترائی میں وہ رہتے ہیں - ان بیچارے تھاروں کے لئے آڑھتی صرف مٹی کا تیل اور کھانے کے لئے تھوڑا سا چاول چھوڑ دیتے ہیں باقی سب کا سب ان سے وصول کر لیتے ہیں - ان کے بچے قرضدار پیدا ہوتے ہیں اور قرضدار مرتے ہیں - ایک طرف تو کسانوں کی یہ لوٹ چلتی ہے ان کی طرف سے اور کسانوں کو تباہ اور برباد زندگی بھر کے لئے کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں - میرے اپنے ضلع کا واقعہ ہے کہ ۲۵ سے ۲۸

روپئے من تک ان آڑھتیوں نے کسانوں سے غلہ خریدا اور اس کو ۶۰ روپئے من سے لے کر ۶۶ روپئے من تک کے بھاؤ پر بیچا - کیا اس بات کو بھلایا جا سکتا ہے کہ جب ۱۹۶۷ میں بنارس میں مظفر پور میں اور بہار میں لوگ بھوکوں مر رہے تھے - ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے رہے تھے اس وقت ان آڑھتیوں کے مکانوں میں چاول کی بوریاں - آٹے کی بوریاں چھتوں سے باتیں کر رہی تھیں -

اتنا ہونے پر بھی آج ان کی یہاں وکالت کی جاتی ہے - اس بات پر غور نہیں کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اس ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے - کتنی تباہی ہو رہی ہے - غلے کا بیوپار ہمارے ملک کا سب سے بڑا بیوپار ہے - لگ بھگ دس کروڑ ٹن غلہ اس ملک میں خریدا اور بیچا جاتا ہے جس پر لگ بھگ پانچ ارب روپئے سے زیادہ منافع کمایا جاتا ہے - یہ جو منافع ہے یہ قوم کے کام میں آنا چاہئے -

میں مانتا ہوں کہ سٹیٹ ٹریڈنگ میں بہت خرابیاں ہیں - بہت زیادتیاں ہوتی ہیں - بڑے کام ہوتے ہیں، بڑا لاس ہوتا ہے - ہمارے بزرگ لوہیا پربھو صاحب نے کہا کہ یہ ملک کا ہی تو نقصان ہوتا ہے - لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ ٹریڈنگ کارپوریشن میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنا بھی تو ہمارا فرض ہے جب

اس کی بات آئیگی تو اسکو بھی ہم سنبھالیں کے - ساتھ کرپشن وسائز کریںگے - اس کو ہم معاف نہیں کرینگے - لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چاہے کوئی سرکاری ادارہ ہو یا غیر سرکاری - تیس روپیے من غلہ خرید کر ۶۶ روپئے من بیچے یا اس انتظار میں رہے کہ کب غلہ مہنگا ہو اور کب بیچا جائے - لوگ بھوکوں مرتے رہیں لیکن یہ اس غلے کو دبا کر بیٹھا رہے -

میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو پارٹی کے نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے - اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ کنور موہن سروپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس پارٹی کی طرف سے یہ پرستاؤ آیا ہے - میں چاہتا ہوں کہ پارٹی لیول سے اوپر اٹھ کر ہم کو اس پرستاؤ کو ایک رائے سے پاس کر دینا چاہئے - میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سرکار تیزی کے ساتھ اس طرف قدم بڑھائے -

اگر یہ ایسا نہیں کریگی تو ایک طرف تو کنزیومرز کی اور دوسری طرف کسانوں کی لوٹ اسی طرح سے چلتی رہے گی - مجھے تو کئی بار شبہ ہوتا ہے اور یہ ایک قدرتی بات بھی ہے کہ کہیں سرکار کی بھی ان بیوپاریوں کے ساتھ ملی بھگت تو نہیں ہے - اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس ریزولیوشن کو اتفاق رائے سے پاس

[شری اسحاق سنبھلی]
کیا جائے اور غلے کی تجارت کو
فوری طور پر نیشنلائز کیا جائے -]

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : सभापति महोदय मैं एक किसान भी हूं और उपभोक्ता भी हूं और सरकार और व्यापारी दोनों का शिकार भी हूं। जब मुल्क में कमी होती है गल्ले की तब तो दूसरी बात है लेकिन जब मुल्क में गल्ले का भाव चौदह रुपये मन था और गल्ला ज्यादा पैदा होता था उस वक्त सरकार ने कहा था कि सौ रुपये मन के भाव पर वह मंडी में गल्ले को खरीदेगी। लेकिन उसने आदेश दे दिया कि पांच सौ मन से अधिक वह नहीं खरीदेगी । जब किसान की गाड़ी मंडी में आई तो लाला ने कहा कि चौधरी तुम्हारा माल सरकार नहीं ले रही है यह जायेगा सात रुपये मन में। एक तो सरकार का यह हिसाब हमने देखा है ।

उसके बाद आकर 1965 में जब हमने देखा कि गल्ले की कमी है तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मुल्क को जरूरत है बेच दो और जाड़ों में जाकर मक्का खरीद लें । मेरी पत्नी ने बहुत इन्कार किया कहा कि न तो यह बढ़िया सरकार है और न ही बढ़िया व्यापारी हैं इस वास्ते साल भर का तो कम से कम खाने के लिए रख लो। लेकिन चूंकि मुल्क को जरूरत थी इस वास्ते उसको मैंने बेच दिया। जब मक्का निकला तो जितने रुपये मन के भाव पर गेहूं बेचा गया था सन् 1966 के जाड़ों में मक्का खरीदा तो उतने ही रुपये में तीस सेर मिला। गेहूं का तो मक्का हो गया और वजन में भी घट गया। यह काम व्यापारियों ने किया ।

हालत यह है कि जिस मुल्क में पैदा करने वाले आदमी को कम पैसा मिलेगा और उसके उत्पादन के बेचने वाले को अधिक पैसा मिलेगा उस मुल्क में बुद्धिमान आदमी भी सुस्त और चालाक होगा और उत्पाद में नहीं लगेगा, बेचने की तिकड़म में लग जायेगा। जिस मुल्क की बुद्धि बेचने में खर्च होने लगेगी उत्पादन में नहीं लगेगी वह मुल्क कंगाल होता चला जाएगा । वही आज मुल्क की हालत होती जा रही है। जब भी कोई काम तय किये जाते हैं तो किसान और उपभोक्ता दोनों की जो असहाय स्थिति है उसका अनुचित लाभ उठाकर तय कर दिये जाते हैं, अनुचित लाभ उठा कर तय कर दिये जाते हैं । सरकार भी जब तय करती है तब भी यही हिसाब लगाती है कि इतना मूल्य मिल जायेगा या नहीं मिलेगा। उस की जो उत्पादन कीमत है उसकी जो लागत कीमत है उसका भी तो हिसाब लगाया जाना चाहिये लेकिन वह कभी नहीं लगाया जाता है ।

हमारे जन संघ वाले और स्वतन्त्र पार्टी वाले इसको कुछ आइड्योलोजिकल सवाल बना रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई आइड्योलोजिकल सवाल है। जापान में मुक्त व्यापार है। वहां तो पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था है। लेकिन आप देखें कि वहां भी फूड की ट्रेड नेशनलाइज्ड है। आपकी फ्री ट्रेड का फ्री इंटरप्राइज का सब से बड़ा जो लकड़दादा अमरीका है वहां भी व्यापारी पूरी तरह से इस ट्रेड को नहीं ले पाया है। झक मार कर वहां सरकार को यह काम करना पड़ता है कि इस सीमा से नीचे अगर कीमतें गिरती हैं तो लाखों टन गल्ला सरकार खरीदती है और ऊपर जब कीमतें जाती हैं तो उस गल्ले को बेचती हैं। पूंजीवाद के द्वारा तो इस मसले को हल किया ही नहीं जा सकता है। सरकार को तो बीच में आना ही पड़ता है अमरीका में भी और जापान में भी ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन हो और आप भी इसको समर्थन प्रदान करें ।

MR. CHAIRMAN: The word *lakad dada* is not in good taste. Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): Mr. Chairman, I thank Shri Mohan Swarup for moving his Resolution on a subject which vitally concerns the life of our people and I appreciate the sentiments expressed by Shri Mohan Swarup and by many of the hon. Members who have expressed their views on the floor of the House. Shri Maharaj Singh Bharati just now referred to the fact that even in a country like Japan there is intervention by Government in food trade. Not only in Japan, but if we examine the trade pattern of many other countries, Italy for instance, we find the paddy trade in Italy is in the hands of the State. So, State intervention is there. Not only in the deficit countries but even in surplus countries like Canada and Australia there is the Wheat Board. Both those countries are surplus from the point of view of wheat production. But even then there is intervention from the State both in the internal trade as well as in the external trade.

SHRI LOBO PRABHU: No control; only purchase.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In a vast country like that of India which is deficit to a certain extent in regard to food, I do not think we can allow *laissez faire* in regard to the food trade.

SHRI PILOO MODY: What is that?

SHRI LOBO PRABHU: Let go.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In fact, a number of expert committees, which have examined this aspect, have also come to the same conclusion. For instance, after the tragedy of 1943 of the Bengal famine, the then Government of India appointed a famine commission to go into the food problem. I do not think even friends of the Swatantra Party or the Jana Sangh will allege that at that time the Government was having any ideological inclinations. But even then the Famine Commission, which submitted its report in 1945, came to the conclusion that to provide food is mainly the responsibility of Government and that Government must intervene in the food trade if it is to provide protection to the people.

So, as far as the point whether Government should interfere in the food trade or not is concerned, it is the primary responsibility of Government to see that foodgrains are made available at a reasonable price to the people at large. Therefore Government must necessarily intervene in the food trade. So, I do not at all agree with the views expressed by Shri Lobo Prabhu and Shri Sharma of the Jana Sangh.

But, at the same time, there are various other aspects of the problem too. Some hon. Members have referred to the problem from the point of view of how the farmer should be assured of a reasonable price. That also is a very important point. The usual phenomenon of trade in this country has been that in the immediate post-harvest period prices get depressed and farmers are left at the mercy of the trading community and as soon as the lean period comes the consumers have to purchase the same foodgrains at a very high price and they are left at the mercy of traders. This is a phenomenon repeated from year to year.

SHRI LOBO PRABHU: You have the powers to acquire and licence grain. What are you doing for acquiring the hoards of foodgrains with traders? Please explain that. The fault is yours.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Not only from the point of view of Government's responsibility or of Government intervening in the food trade but even from the point of view of assuring, remunerative or reasonable prices to the farmers and, at the same time, ensuring availability of foodgrains to the consumers at reasonable prices, I think, Government owes some responsibility and in our country we have to develop public sector agency which will take care of this.

So, as far as the general sentiment expressed by hon. Member Shri Mohan Swarup is concerned, I am completely in agreement with him. But I do not share the sentiment of some hon. Members who from the ideological point of view say that everything should be nationalised. I do not agree with that view also; but, at the same time, we should not have an allergy as some Swatantra Members are allergic. Whenever the word 'nationalisation' or 'socialisation' of food trade comes in, they are very allergic.

SHRI PILOO MODY: The very fact that you mention that the Government must interfere is in itself a very unfortunate choice of words. What you should say is "regulate" and not "interfere".

SHRI ANNASAHIB SHINDE: But we have to take a practical view in this matter. In our country we must proceed on the assumption that we must develop a public sector organisation and to see that the public sector organisation gets a commanding position in the food trade. That is why the Government of India established the Food Corporation of India and the Food Corporation of India is for the first time in a very big way in the food trade. We have been assuring the farmers now that we shall be prepared to purchase foodgrains not only at the minimum price or the support price but we shall be purchasing foodgrains at the procurement price.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Can you give the firm assurance to the farmers that you will not reduce the procurement price?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: May I assure Shri Gupta, this House and the farmers of this country that we stand firm by this that we shall be prepared to purchase any quantity offered by farmers at the procurement price. That is why the State Bank of India has placed about Rs. 120 crores at the disposal of the Food Corporation of India. Moreover, in addition to that, Rs. 39 crores have been advanced to the Food Corporation of India by way of loans, and in this Budget also which is before the House, about Rs. 40 crores have been provided so that, as and when it requires, the amount may be made available to the Corporation. So, we should see that the Food Corporation really gets a commanding position in the food trade. But the difficulty in this country is that we have to see that public opinion is educated so that the public sector organisation really gets necessary cooperation from the various State Governments from the public bodies and from the various parties as such.

I would appeal to the House and to the Members of the Swatantra Party and Jana Sangh, particularly, that they should not have ideological bias against this because the Government do not proceed on the assumption of any ideological bias as such but take into consideration the vital interest of the masses and the farmers and the food economy of the country because stabilisation of food economy is very important. I hope all the Members of the House will give necessary cooperation to the Government of India and see, in times to come, that the Food Corporation plays a very important role in our country, I wish to extend the same appeal to the various State Governments.

SHRI LOBO PRABHU: Why don't you take the trouble of giving the

reason why you disagree with my proposition? I put a very clear proposition. You create artificial scarcity, you create high prices and you are the cause of the food problem in the country. Please answer that question.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I have already covered his point. Free trade was having full play in this country. There was no curb on free trade and that led to this phenomenon. That is why if the Food Corporation comes more and more in the food trade, all these things can be eliminated.

SHRI SONAVANE (Pandharpur): It was because of the free trade that these people fleeced the farmers and the consumers.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I would appeal to the hon. Member to withdraw the Resolution, not to press for it because I have expressed my views and the Government shares his sentiments. At the same time, it is not necessary to press this Resolution because it will not serve any purpose. I do not think the stage has come when we can really do anything more than what the Government is already doing in the field.

श्री इसहाक सामभजी : वह टाइम कब आयेगा, जब लूट-खसोट बन्द की जायेगी ?

श्री मोहन स्वरूप : सभापति महोदय, मैं अपने दोस्तों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। साथ ही साथी दूसरे दोस्तों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इसमें भाग लिया—चाहे वे इस तरफ के हों या कांग्रेस की तरफ के लोग हों। हर आदमी यह पसन्द करेगा कि कीमतें बढ़ने से रोकी जाए, साथ ही साथ यह भी चाहेगा कि बाहर से हम गल्ला आयाता न करें —चाहे लीतो प्रभू हों या दूसरे लोग हों। हर आदमी आज यह भी चाहेगा कि किसानों को उसकी पैदावार का, उसकी उपज का उचित भाग मिले। लेकिन मैं कह सकता हूं, सभापति महोदय, जो स्थिति इस वक्त चल रही है, जैसा कि मेरे दोस्त ने यहां पर नक्शा खींचा, मैं समय के अभाव के कारण वह नहीं कह सका। इस स्थिति में भी किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। किसान एक एसी भेड़ के समान है, जिस को जो चाहता मूड़ लेता है।

दूसरी बात—किसान इस वक्त देश में संगठित नहीं हैं उस को संगठित होने से रोका गया है। चाहे कोई भी ज़माना आया—अंग्रजों का ज़माना आया या कांग्रस का ज़माना आया—किसान को संगठित होने से सदैव रोका जाता है, क्योंकि सरकार डरती है कि अगर ये संगठित हो गये तो वह एक ऐसी शक्ति होगी, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकेगा। लेकिन अब वक्त आ रहा है, किसानों में चेतना आ रही है और अब वह समय दूर नहीं है जबकि वह संगठित हो कर रहेगा। जैसा मैंने अभी अर्ज किया था—किसान ही एक एसा बदनसीब तबका है इस समाज में, जिस को कि अपनी उपज का मूल्य निर्धारित करने का स्वयं अधिकार नहीं है। लेकिन अब वह समय आ रहा है, शायद बहुत जल्द आयेगा, जब कि किसान संगठित होंगे और उन को अपना पेट भरने का, अपनी रीट ह सिल करने का हक उन्हें प्राप्त होगा।

जो वर्तमान स्थिति चल रही है उस से काम चलने वाला नहीं है। मैं शिंडे साहब और सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रीयकरण की तरफ पग बढ़ायें क्योंकि यह कैंसर जैसी पुरानी बीमारी हो गई है जिसको काट डालने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं ज्यादा समय न लेकर केवल

[श्री मोहन स्वरूप]

यही अनुरोध करूंगा कि जो मेरा प्रस्ताव है उसको स्वीकार करने की कृपा करें और उसे कार्यान्वित करने की बात सोचें, तभी किसानों और उपभोक्ता दोनों का लाभ हो सकता है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I appeal to the hon. Member not to press his Resolution.

MR. CHAIRMAN: Is he willing to withdraw his Resoltuion?

सभापति महोदय : क्या आप प्रस्ताव को वापिस करना चाहते हैं ?

श्री मोहन स्वरूप : मन्त्री जी के इस आश्वासन के बाद कि वे गम्भीरता से इस पर विचार करेंगे, मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

MR. CHAIRMAN: Has he the leave of the House to withdraw his Resolution?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The next Resolution is that of Mr. N. K. Somani.

About the fourth Resolution, I want to make this clear. The Second Resolution was started, at 4.40; even if it had been completed within one hour, the Fourth Resolution could not come because now Mr. Somani's Resolution is there and then at 6.30 we have got a half-an-hour discussion.

SHRI S. XAVIER: I shall just move it, Sir.

MR. CHAIRMAN: Unless Mr. Somani's Resolution is disposed of, how can that be taken up?

SHRI LOBO PRABHU: He may just be allowed to move his Resolution and he can continue on the next occasion. That is an important Resolution.

MR. CHAIRMAN: But Mr. Somani's Resolution has to be disposed of and then only it can be taken up.

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur): After my Resolution, you may allow him just to move.

SHRI PILOO MODY: If Mr. Somani's Resolution is finished by 6.25 P.M., then Mr. Xavier can be allowed to move his Resolution.

MR. CHAIRMAN: Even if it finishes at 6.30, I have no objection to Mr. Xavier' moving his Resolution. I do agree that it is a very important Resolution.

Now Mr. Somani.

17.52 hrs.

RESOLUTION RE: REMOVAL OF ZONAL RESTRICTIONS ON MOVEMENT OF FOODGRAINS

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur): I beg to move:

> "This House is of opinion that in view of increased food production during the current year, zonal restrictions on the movement of foodgrains be removed forthwith."

We have heard from almost all the speakers who participated in the previous Resolution that food is an item or a subject of discussion which should not have any ideological barriers or should not have State or party barriers. But unfortunately from what we have seen and from what has been the experience in the last few years, one is constrained to come to the conclusion that even in regard to such a vulnerable, such a needy, such